



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 195]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जुलाई 19, 2001/आषाढ़ 28, 1923

No. 195]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 19, 2001/ASADHA 28, 1923

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2001

सं. टीएमपी/23/2001-सीएचपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार ग्रेब के किराया प्रभार के निर्धारण के लिए चेन्नई पत्तन न्यास के प्रस्ताव का निपटान करता है।

अनुसूची

मामला सं. टीएमपी/23/2001-सीएचपीटी

चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी)

आवेदक

आदेश

(जून, 2001 के 28वें दिन पारित किया गया)

यह मामला ग्रेबों के किराया प्रभार के निर्धारण के लिए चेन्नई पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. सीएचपीटी ने अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित मुख्य बातों का उल्लेख किया है:

- (i) सीएचपीटी की दरों के मान में 1 1/2 घन गज और 2 1/2 घन गज की क्षमता के ग्रेब के लिए किराया प्रभार क्रमशः 592/- रुपए और 974/- रुपए निर्धारित है।
- (ii) सरकारी लेखापरीक्षा में उल्लेख किया गया है कि यद्यपि दरों के मान में किराये के लिए दो मित्र दरें उपलब्ध हैं, फिर भी सीएचपीटी क्षमता पर, जोकि उपयुक्त नहीं है, विचार किए बिना क्रेनों के साथ जुड़े हुए ग्रेबों के लिए 296/- रुपए प्रति पारी की दर (संशोधन-पूर्व दर) से किराया प्रभार वसूल कर रहा है।

- (iii) यातायात प्रचालनों के लिए 1 1/2 घन गज और 2 1/2 घन गज क्षमता वाले ग्रेब को बदलकर पहले ही 3.5 घन मीटर के और 4 घन मीटर के ग्रेब लगा दिए गए थे। लेखापरीक्षा द्वारा की गई आपत्ति के मद्देनजर अगस्त, 1997 से 3 1/2 घन मीटर के ग्रेब के लिए 1000/- रुपए और 4 घन मीटर के ग्रेब के लिए 1,100/- रुपए की अस्थायी दर से वसूली की गई थी।
- (iv) अस्थायी दरों का निर्धारण दरों के मान में दिए गए उपबंध के अनुसार किया गया था, जिसमें सीएचपीटी के अध्यक्ष को उन जलयानों अथवा साधित्रों के प्रयोग के लिए प्रभार निर्धारित करने की विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। जिनके लिए दरों के मान में प्रशुल्क निर्धारित नहीं किए गए हैं।
- (v) ग्रेबों के किराया प्रभार अब लागत के आधार पर 3.5 घन मीटर की क्षमता के ग्रेब के लिए 1,000/- रुपए और 4 घन मीटर की क्षमता के ग्रेब के लिए 1,100/- रुपए निश्चित किया गया है।
- (vi) परंतु, दोनों ग्रेबों के लिए 8 घंटे की अवधि के लिए 1000/- रुपए और 4 घंटे अथवा उसके किसी हिस्से के लिए न्यूनतम 500/- रुपए की एकसमान दर अपनाने का प्रस्ताव किया गया है।

2.2 उपर्युक्त संदर्भ में सीएचपीटी द्वारा दरों के मान में निम्नलिखित संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है:

- (i) पुस्तिका-I, अध्याय-IX, मान-घ के अंतर्गत - प्लवमान जलयान, साधित्र आदि के लिए प्रभार, श्रेणी-II में क्रम सं. 8 के पश्चात नए क्रम सं. 9 को निम्नवत् जोड़ा जाए :

क्रम संख्या और विवरण	किराये की दर (रुपयों में)	किराये की अवधि	न्यूनतम (रुपयों में)	टिप्पणी
9. किसी भी क्षमता की तट क्रेन के साथ जुड़ा हुआ ग्रेब (3.5 घन मीटर और 4 घन मीटर)	1,000/-	8 घंटे की प्रति अवधि	500/-	(क) न्यूनतम प्रभार चार घंटे अथवा उसके किसी हिस्से के लिए होगा। (ख) ग्रेब के लिए किराया प्रभार, जहाँ बर्थ किराया प्रभारों में तट (घाट) क्रेन का प्रयोग शामिल है, उसे छोड़कर जिस क्रेन के साथ ग्रेब जुड़ा है उस क्रेन के किराया प्रभारों से अतिरिक्त होगा।

- (ii) दरों के मान की पुस्तिका-I में अध्याय-XI, बर्थ किराया, के अधीन वर्तमान क्रम सं. 3, को हटाकर उसके स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:

“3. बोर्ड की दरों के मान के अध्याय-IX की श्रेणी-II (जैसा कि नं. 7 से 9) मान-घ के अधीन किए गए उपबंध के अनुसार ग्रेबों (तट क्रेनों से जुड़े हुए) का किराया जब कभी इन दरों पर जलयान की लदाई और अवतारण कार्य के बल्क कार्गो के प्रहस्तान के लिए किराये पर लिया जाए।”

2.3. इसके अलावा 10 अप्रैल, 2000 से प्रमावी क्रेन-माफ़ा की दरों के मान के सामान्य संशोधन में महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित उपयुक्त प्रतिशत वृद्धि लागू करके प्रस्तावित दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है। (इस प्राधिकरण ने सीएचपीटी के मामले में अपने 22 मार्च, 2000 के अपने आदेश द्वारा जिसे 10 अप्रैल, 2000 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। क्रेन भाड़ा/एफएलटी के लिए 100% वृद्धि का अनुमोदन किया था)।

3. सीएचपीटी के प्रस्ताव को सभी संबद्ध प्रयोक्ताओं/पत्तन प्रयोक्ताओं की प्रतिनिधि संस्थाओं को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था। उनसे प्राप्त टिप्पणियों का सार निम्नलिखित है:

चेन्नई सीमा-शुल्क हाऊस एजेंडस संघ (सीसीएचएए)

चेन्नई पत्तन न्यास द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव युक्तिसंगत है।

तमिलनाडु बिजली बोर्ड (टीएनईबी)

- (i) ग्रेब किराया प्रभार को 296/- रुपए से बढ़ाकर 1000/- रुपए प्रति पारी करने का प्रस्तावित संशोधन बहुत अधिक और अनुचित है। प्रस्तावित वृद्धि लगभग 350% है।
- (ii) इस वृद्धि से कोयले की आयात लागत में पर्याप्त वृद्धि होगी, जिससे उत्पादन की लागत में वृद्धि होगी और परिणामस्वरूप तमिलनाडु की जनता प्रभावित होगी।
- (iii) टीएनईबी को विशेष हैसियत दी जाए और उसे ग्रेब के किराया प्रभारों में प्रस्तावित वृद्धि से छूट दी जाए।

भारतीय राष्ट्रीय पोतस्वामी संघ (आईएनएसए)

- (i) किराया प्रभारों के परिकलन में 225 पारियों पर विचार करने का आधार स्पष्ट नहीं किया गया है।
- (ii) पूंजी पर 18% की दर पर प्रतिलाम का विचार एकाधिकार-वादी है। यह 12% से अधिक नहीं होगी।
- (iii) दोनों ग्रेबों के लिए दरों का पूर्णांकन पत्तन के पक्ष में किया गया है।

भारतीय जहाज़रानी निगम (एससीआई)

- (i) सीएचपीटी ने ग्रेब का कार्यकाल का अनुमान 5 वर्ष लगाया है, जोकि बहुत कम है। प्रहस्ति किए जाने वाले कार्गो के स्वरूप को देखते हुए पारियों की संख्या लागत-पत्र में मानी गई 225 पारियों के बजाय कम से कम 360 होगी। तब प्रति पारी लागत 3.5 घन मीटर ग्रेब के लिए 617/- रुपए और 4.00 घन मीटर ग्रेब के लिए 647/- रुपए होगी।
- (ii) सीएचपीटी ने महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण से 10 अप्रैल, 2000 को भारत के राजपत्र में प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित दरों के मान में सामान्य संशोधन से संबंधित आदेश में अनुमोदित प्रशुल्क वृद्धि लागू करते हुए निर्धारित दरों में 100% वृद्धि का अनुमोदन करने का अनुरोध किया है। परिणामस्वरूप, सीएचपीटी 8 घंटे के लिए 2000/- रुपए और 4 घंटे अथवा उसके किसी हिस्से के लिए न्यूनतम 1000/- रुपए की राशि वसूल करने का प्रस्ताव कर रहा है, जोकि बहुत अधिक है।
- (iii) चूंकि सीएचपीटी द्वारा प्रस्तुत लागत-पत्र में उक्त ग्रेबों के लिए 1000/- रुपए प्रति पारी का आँकड़ा दर्शाया गया है, अतः लागत-पत्र में दर्शाई गई अधिक लागत राशि का अनुमोदन मांगना तर्कसंगत अथवा युक्तिसंगत नहीं होगा।
- (iv) सीएचपीटी पहले से ही अगस्त, 1997 से 3.5 घन मीटर के ग्रेबों के लिए 1000/- रुपए और 4.00 घन मीटर के ग्रेबों के लिए 1100/- रुपए की अस्थायी दर वसूल कर रहा है। ये आँकड़े उसके लागत-पत्र में निर्दिष्ट प्रति पारी लागत के अनुसार हैं। इसलिए, वही दरें रखने का प्रस्ताव किया गया है।

चेन्नई पत्तन पोतवणिक संघ (सीपीएसए)

चेन्नई पत्तन पर बल्क यातायात में पूरी तरह मंदी है और महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा 10 अप्रैल, 2001 से अनुमोदित प्रतिशत लागू करके कोई और वृद्धि करना व्यापार के हित में हानिकारक होगा।

चेन्नई स्टीमर एजेंट संघ (सीएसएए)

ग्रेब के प्रयोक्ता अधिकांशतः पोतवणिक हैं। संबद्ध प्रयोक्ता संस्था द्वारा, जोकि इस मामले में चेन्नई पत्तन पोतवणिक संघ है, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण का मार्गदर्शन किया जाए।

4. प्रयोक्ताओं द्वारा भेजी गई प्रत्येक टिप्पणी की एक प्रति प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में सीएचपीटी को भेजी गई थी। सीएचपीटी ने प्रतिपुष्टि सूचना पर आगे निम्नलिखित टिप्पणियाँ की हैं:

- (i) टीएनईबी द्वारा 1 1/2 घन गज के ग्रेब के लिए दी गई 296 रुपए प्रति पारी की दर को संशोधित करके 10 अप्रैल, 2000 से 592 रुपए प्रति पारी कर दिया गया है।
- (ii) इन ग्रेबों की उच्चतर वहन/प्रहस्तन क्षमता पर विचार करते हुए दोनों 3.5 घन मीटर और 4 घन मीटर के ग्रेबों के लिए प्रस्तावित 1000/- रुपए की दर 2 1/2 घन गज के ग्रेब के लिए 487 रुपए की संशोधन-पूर्व दर की तुलना में अधिक तर्कसंगत है।
- (iii) किसी भी पत्तन प्रयोक्ता को ऐसे ग्रेब के किराया प्रभार में रियायत नहीं दी जा सकती।
- (iv) ग्रेब का अनुमानित कार्यकाल (तात्कालिक) भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा निर्धारित विभिन्न वस्तुओं के कार्यकाल मानकों के अनुसार 5 वर्ष माना गया है।
- (v) किराया प्रभारों के परिकलन में 225 पारियों की गणना कार्य निष्पादन के पूर्व औसत के आधार पर की गई है।
- (vi) दरों के भान के सामान्य संशोधन में महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कोई भी वृद्धि पहले से प्रयोग किए जा रहे साधित्रों/उपकरणों पर लागू होगी। चूंकि ग्रेबों का प्रयोग 1997 से किया जा रहा है, इसलिए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा 10 अप्रैल, 2001 को यथा अनुमोदित 100% वृद्धि 1000/- रुपए प्रति पारी की प्रस्तावित दर पर लागू होती है। यह 10 अप्रैल, 2001 से पूर्व-प्रभाव से लागू होगी।

5. इस मामले में संयुक्त सुनवाई 9 मई, 2001 को सीएचपीटी परिसर में की गई थी। संयुक्त सुनवाई के समय निम्नलिखित निवेदन किए गए थे:

चेन्नई पत्तन न्यास

- (i) नये ग्रेब अतिरिक्त लगाए गए हैं, प्रतिस्थापन नहीं किया गया है।
- (ii) सरकारी परिपत्र में भी ग्रेब का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है।
- (iii) अब किराया प्रभार को 3.5 घन मीटर/4 घन मीटर की क्षमता के ग्रेब के लिए 1000/1100 रुपए प्रति पारी की अस्थायी दर से बढ़ाकर 2000/- रुपए प्रति पारी करने का प्रस्ताव है।
- (iv) हमने पारियों की औसत संख्या को लिया है। हमें नहीं मालूम कि एससीआई ने कैसे कहा कि ये पारियाँ 225 नहीं 360 होंगी।
- (v) अप्रैल, 2000 के सामान्य संशोधन प्रस्ताव में इन ग्रेबों की दरों को नियमित करने का प्रस्ताव किसी प्रकार छूट गया था।
- (vi) हम लागत में बचत, दक्षता में सुधार आदि के लिए कई उपाय कर रहे हैं। परंतु ये ग्रेब के लिए संगत नहीं हैं क्योंकि यह एक बहुत छोटा उपस्कर है।
- (vii) हम 1989 से 1991 तक कम दर वसूल करते रहे हैं। वर्ष 2000 तक प्रशुल्क में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। वर्तमान दर वास्तविक आँकड़ों पर आधारित है। यदि हमने अप्रैल, 2000 में यह प्रस्ताव किया होता तो हमें 100% वृद्धि प्राप्त होती।
- (viii) हमने इन ग्रेबों के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल केवल 1997 से लागू किया है।
- (ix) हमें निर्यात पर विचार करते हुए ग्रेबों की सुरक्षा के लिए और उर्वरक बर्ध से कोयला बर्ध में परिवहन समय के कारण भी ग्रेब के प्रयोग को उर्वरक के लिए सीमित करना होगा।

तमिल वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल (टीसीसीआई)

- (i) किसी ग्रेब के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल बहुत कम है। इसका बहुत अधिक प्रयोग नहीं किया जा रहा है इसलिए इसका कार्यकाल बहुत अधिक होगा।

- (ii) 2 1/2 घन मीटर की क्षमता के ग्रेब की वर्तमान दर 974/- रुपए प्रति पारी है। 3.5 घन मीटर की क्षमता के ग्रेब के लिए किराया प्रभार 2000/- रुपए प्रति पारी प्रस्तावित है। यह कोई तार्किक समीकरण नहीं है।
- (iii) ग्रेब कार्य कम से कम छह माह और एक दिन में दो पारियों में होता है। इस प्रकार हमने 360 पारियों तय की हैं।
- (iv) इन ग्रेबों के लिए भी रखरखाव मरम्मत आवश्यक है। यह डाउनटाईम है। इसीलिए हमने कहा है कि इन ग्रेबों का कार्यकाल अधिक होना चाहिए।
- (v) 100% का अप्रैल, 2000 संशोधन 1991 की दरों के अनुसार था। ग्रेब की दरें अगस्त, 1997 में निर्धारित की गई थीं। इस (नवीन) आधार पर एमबीपीटी को 100% वृद्धि के लिए नहीं कहा जा सकता।

सीपोर्ट लोजिस्टिक्स

- (i) 100% वृद्धि का कोई औचित्य नहीं है। ग्रेब 1500 मीट्रिक टन के मानक के स्थान पर केवल 200 मीट्रिक टन प्रति पारी प्रति जहाज प्रहस्तन करता है।

ए.एम. अहमद कम्पनी

- (i) उन्होंने यह कहा है कि यह प्रत्याशित संशोधन है। परंतु, सीएचपीटी ने बल्क उर्वरक के प्रहस्तनकर्ताओं से बकाया राशि की मांग की है। पत्तन प्रयोक्ताओं की बैठक में इस पर चर्चा की गई थी, परंतु कोई निर्णय नहीं लिया गया था। हमें निविदा प्रयोजनों के लिए 'कोई बकाया राशि नहीं' का प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है।

40 भोरुका स्टील

- (i) 3.5 घन मीटर की क्षमता का ग्रेब 1989 में खरीदा गया था, परंतु इसकी गणना अभी तक की जा रही है। 5 वर्ष के कार्यकाल पर विचार कहां किया गया है?
- (ii) 1989 के ग्रेब के लिए 1997 के 1000/- रुपए से 100% वृद्धि नहीं की जा सकती। यदि सीएचपीटी ऐसी वृद्धि चाहता है तो उन्हें ग्रेब बदलना होगा।
- (iii) 225 पारियों का आँकड़ा बहुत कम है। हम एससीआई के तर्क का समर्थन करते हैं।

एसआईसीएल

- (i) यदि ग्रेब खराब हो जाता है तो क्या हमें कोई छूट मिलेगी? दरों के मान में छूट का प्रावधान अवश्य होना चाहिए। ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों में श्रमिक दल को भी बेकार बैठना पड़ेगा। उस स्थिति में हमें नुकसान होगा।
- (ii) ग्रेब केवल उर्वरक के लिए प्रयोग किया जाता है। कोयले को अलग नहीं रखा जा सकता। यदि इससे ग्रेब की उपयोगिता बहेगी तो लागत कम हो जाएगी।

तमिलनाडु बिजली बोर्ड (टीएनईबी)

- (i) ग्रेब 1989 से कार्य कर रहा है। कृपया इस बात को ध्यान में रखा जाए कि यह 12 वर्ष से कार्य कर रहा है। उन्हें परिसंपत्ति की लागत पर मूल्यहास और ब्याज से 198% प्रतिलाम हो रहा है, जोकि सही नहीं है।
- (ii) 225 पारियाँ बहुत कम प्रतीत होती हैं। परंतु, यदि यह वास्तविक औसत है तो हमें यह स्वीकार करना होगा।

7. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में और संयुक्त सुनवाई के दौरान दिए गए तर्कों पर विचार करने पर निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है:

- (i) सीएचपीटी अगस्त, 1997 से 3.5 घन मीटर और 4 घन मीटर की क्षमता के ग्रेबों के लिए क्रमशः 1000/- रुपए और 1,100/- रुपए की अस्थायी दर वसूल कर रहा है। इन अस्थायी दरों का निर्धारण सीएचपीटी द्वारा

224761/2001-2

संशोधन-पूर्व दरों के मान में दिए गए उपबंध के आधार पर किया गया था जिसमें उनके अध्यक्ष को उन साधित्रों/जलयानों के लिए प्रशुल्क निर्धारित करने की विवेकाधीन शक्तियाँ दी गई थी, जिनके लिए दरों के मान में प्रशुल्क निर्धारित नहीं थे। यदि प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए ऐसी विवेकाधीन शक्तियाँ विनियमित अधिकारियों को सौंपी जाती हैं तो यह प्रशुल्क निर्धारण के लिए महापत्तन न्यास अधिनियम में परिकल्पित व्यवस्था के अनुसार उचित नहीं होगा। इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए, सीएचपीटी के अध्यक्ष को वैवैकिक शक्तियाँ देने वाले इस उपबंध को इस प्राधिकरण द्वारा 30 मार्च, 2001 को अधिसूचित संशोधित दरों के मान में से पहले से ही हटा दिया गया है।

- (ii) सीएचपीटी अगस्त, 1997 से अस्थायी दर वसूल कर रहा है और अब उसने दोनों ग्रेबों के लिए 1000/- रुपए के लागत आधारित प्रशुल्क का परिकलन किया है। दरें चूंकि अस्थायी थीं अतः सीएचपीटी के लिए तत्काल उपलब्ध अवसर पर इस प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करके उन्हें नियमित करना अत्यावश्यक था। परंतु सीएचपीटी ने वर्ष 2000 में प्रभावी प्रशुल्कों के सामान्य संशोधन के समय भी ऐसा नहीं किया। दुर्भाग्य की बात है कि सीएचपीटी ने अपने प्रभारों की 'अस्थायी' वसूली को विनियमित कराने की कार्यवाई करने में लगभग चार वर्ष का समय लगा दिया।
- (iii) सीएचपीटी ने 1997 से परिसंपत्तियों के मूल्यहास की गणना के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल माना है। टीसीसीआई का यह दावा है कि ग्रेब का 5 वर्ष का कार्यकाल बहुत कम है, स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि सीएचपीटी ने सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर 5 वर्ष के आर्थिक कार्यकाल पर विचार किया है। संयोगवश, हम सभी महापत्तनों पर प्रशुल्क के परिकलन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कार्यकाल-मानक की अनुमति देते हैं। इसलिए सीएचपीटी द्वारा अनुमानित मूल्यहास आंकड़े को संशोधित करने की आवश्यकता नहीं है। उपर्युक्त निर्णय पर बिना किसी पूर्वाग्रह के इस मामले में टीएनईबी द्वारा किसी एक ग्रेब के 'कार्यकाल' के बारे कही गई बात विचारणीय है। जैसा कि उनके द्वारा कहा गया है और सीएचपीटी द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि उनमें से एक ग्रेब 1989 से अर्थात् 12 वर्षों से कार्य कर रहा है और अभी तक भी उसे बेकार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

यहाँ विचारार्थ तीन बातें हैं:

- (क) इस परिप्रेक्ष्य में, क्या 5 वर्ष के कार्यकाल निर्धारण को तर्कसंगत कहा जा सकता है?
- (ख) जैसा कि मै0 मोरुका स्टील द्वारा मांग की गई है, यदि प्रशुल्क में किसी वृद्धि पर विचार किया जाता है तो क्या सीएचपीटी को पुराने ग्रेब को बदलकर नया ग्रेब लगाना होगा?
- (ग) जैसा कि टीएनईबी द्वारा अभ्यावेदन किया गया है, पूर्ण रूप से भुगतान वाली इस परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ है। इसलिए, क्या सीएचपीटी को इस मामले में भिन्न रूप में प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए कहा जाना चाहिए ?

जैसा कि पहले कहा गया है, यह प्राधिकरण सरकार द्वारा निर्धारित कार्यकाल-मानक स्वीकार करता रहा है। इस मामले में इस प्रकार निर्धारित कार्यकाल-मानक 5 वर्ष है। ऐसी स्थिति में, मानक में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण रूप से भुगतान वाली परिसंपत्ति के बारे में टीएनईबी द्वारा कही गई बात पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि पूर्णतः भुगतान वाली परिसंपत्तियों को 'निवल ब्लॉक' में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि उसकी गणना नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ के परिकलन के प्रयोजन से की जाती है। तथापि, यह विचार किया जाता है कि क्या वर्तमान दर पर प्रशुल्क के आधार में इस कारक का तत्व शामिल है। ऐसा तभी हो सकता है जब यह प्राधिकरण मार्जिनल लागत मूल्य-निर्धारण प्रणाली को अपनाने की स्थिति में हो, इस प्रणाली को लागू करना जटिल कार्य है और हर हाल में यह अभी विचार-विमर्श के प्राथमिक स्तर पर है। परंतु, मै0 मोरुका स्टील की माँग ध्यान देने योग्य है। यदि सीएचपीटी ऐसे उपकरण के लिए प्रशुल्क में वृद्धि करता है जिसका प्रचालन उसके तकनीकी कार्यकाल के समाप्त होने के बाद भी अधिक किया जा रहा है तो प्रयोक्ता पुराने उपकरण के स्थान पर नया उपकरण लगाने की तर्कसंगत अपेक्षा कर सकता है। इसलिए, सीएचपीटी को यह सुझाव दिया जाता है और उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अगले (संबद्ध) संशोधन के समय इस बात को पूरा करे।

- (iv) सीएचपीटी ने इस प्राधिकरण द्वारा सरकारी ऋणों पर 13.5% ब्याज और विकास निधि तथा नवीनीकरण निधि पर 6% (3+3) ब्याज की गणना करते हुए अन्य मामलों में स्वीकृत 19.5% के मुकाबले 18% प्रतिलाभ पर विचार किया है। 1.5% का यह अंतर लगभग 26 से 28 रुपए प्रति पारी पड़ेगा। चूंकि सीएचपीटी ने 3.5 घन मीटर और 4 घन मीटर की क्षमता के ग्रेबों के लिए 987/- रुपए और 1036/- रुपए की दरों को 1000/-

रुपए और 1100/- रुपए में पूर्णकृत कर दिया है इसलिए 26/- रुपए की सीमा तक आरओसीई कार्य में संशोधन नगण्य होगा और इसीलिए उसे नज़रअंदाज कर दिया गया है।

- (v) टीसीसीआई और कुछ अन्य प्रयोक्ताओं ने दावा किया है कि सीएचपीटी द्वारा उल्लिखित 225 पारियों बहुत कम हैं और किराया प्रभारों के परिकलन में कम से कम 360 पारियों की गणना की जाए। परंतु, सीएचपीटी ने स्पष्ट किया है कि उनके द्वारा उल्लिखित 225 पारियों पूर्व वास्तविक आँकड़ों के औसत पर आधारित हैं। इस संदर्भ में, सीएचपीटी का अनुमान उपयुक्त लगता है क्योंकि वे पूर्व वास्तविक आँकड़ों के औसत पर आधारित हैं और इसीलिए उसे स्वीकार किया जाता है। विशेष रूप से, मुख्य प्रयोक्ता टीएनईबी ने भी स्वीकार किया है कि 'यदि सीएचपीटी का परिकलन वास्तविक आँकड़ों के औसत पर आधारित है तो उसे स्वीकार किया जा सकता है।'

- (vi) हालांकि दो ग्रैबों के लिए लागत अनुमान भिन्न-भिन्न है, फिर भी सीएचपीटी ने दोनों ग्रैबों के लिए एकसमान प्रशुल्क का प्रस्ताव किया है। सीएचपीटी द्वारा वसूल की जा रही अस्थायी दरों और लागत के आधार पर प्रस्तावित दरों में कोई विशेष अंतर नहीं है। उपर्युक्त (iii) (iv) और (v) में चर्चित बातों पर विचार करते हुए भी सीएचपीटी द्वारा प्रस्तावित दर उपयुक्त पाई गई है और इसलिए अनुमोदित की जाती है।

- (vii) यह प्राधिकरण तब तक सामान्यतः पूर्व-प्रभाव से प्रशुल्कों का अनुमोदन नहीं करता जब तक कोई आपवादिक विशेष परिस्थिति न हो। चूंकि इन ग्रैबों का प्रयोग 1997 से किया जा रहा है जिनके लिए अभी भी अस्थायी दरें वसूल की जा रही हैं, इसलिए अगस्त, 1997 से पूर्व प्रभाव से सीएचपीटी द्वारा वसूल किए जा रहे अस्थायी किराया प्रभारों पर सीएचपीटी द्वारा की गई कार्रवाई का समर्थन करने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन के लिए विचार करने की आवश्यकता है। परंतु, सीएचपीटी को भविष्य में इस प्राधिकरण के समक्ष ऐसे 'संपन्न कार्य' मामले प्रस्तुत करने में संयम रखने का सुझाव दिया गया है। सीएचपीटी ने अब दोनों ग्रैबों के लिए एक दर का प्रस्ताव किया है, जबकि इससे पूर्व उन्होंने अपनी अस्थायी व्यवस्था में दो भिन्न दरें अपनाई थीं। अब प्रस्तावित एक ही दर सरलीकरण की ओर एक कदम है और चूंकि दर कम रखी गई है, इसलिए इसे प्रयोक्ताओं को रियायत देना भी कहा जा सकता है। परंतु, संयोगवश इस रियायत से कुछ मामलों में कुछ 'अधिक वसूली' के बारे में बात उठती है। सीएचपीटी के निःस्वार्थ आशयों को ध्यान में रखते हुए जिसके कारण (अप्रत्याशित) समस्या उठी है, सीएचपीटी से वसूल किए गए 'अतिरिक्त प्रभार' को वापस करने के लिए कहना आवश्यक नहीं होगा।

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह प्राधिकरण संशोधित प्रशुल्कों को दो चरणों में अनुमोदित करने का निर्णय करता है। प्रथम चरण में (अर्थात् अगस्त, 1997 से इस आदेश के अधिसूचित होने की तारीख तक) सीएचपीटी द्वारा वसूल की जा रही 'अस्थायी दरें' और द्वितीय चरण में (अर्थात् इस आदेश के अधिसूचित होने की तारीख से आगे) दोनों ग्रैबों के लिए 1,000/- रुपए की एकल दर।

- (viii) सीएचपीटी ने अप्रैल, 2000 के सामान्य संशोधन के मामले में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क वृद्धि के आधार पर किराया प्रभार में 100% वृद्धि का प्रस्ताव किया है।

इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि सामान्य संशोधन के मामले में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क वृद्धि लागत विवरण में दर्शाई गई अधिशेष/घाटे की स्थिति के आधार पर थी। सीएचपीटी ने सामान्य संशोधन के प्रस्ताव में इन दो ग्रैबों के प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए कोई उपबंध शामिल नहीं किया था। इसलिए, यह प्रतीत होता है कि इन ग्रैबों के लिए संगत लागत तत्वों को उस समय प्रस्तुत किए गए लागत विवरण में शामिल नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में, सीएचपीटी द्वारा अब प्रस्तावित दो ग्रैबों के लिए लागत आधारित प्रशुल्क पर 100% की वृद्धि का अनुमोदन नहीं किया गया है।

इसके अलावा, इस संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य भी युक्तिसंगत है:

- (क) किराया प्रभार अनुमानों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। सीएचपीटी द्वारा ग्रैबों के किराये पर पिछले 4 वर्ष के दौरान हुई वास्तविक आय और व्यय का प्रावधान नहीं किया गया है।
- (ख) नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ परिसम्पत्ति के अवमूल्यित मूल्य पर आधारित है। इस मामले में प्रतिलाभ निर्धारित करने के लिए अर्जन लागत को लिया गया है, क्योंकि किराया प्रभारों के परिकलन सुविधा की लागत के आधार पर किया गया है। यदि गतिविधि/सेवा की लागत पर विचार किया जाता है, जैसा कि प्रशुल्क के सामान्य संशोधन के मामले में किया गया है, तो ग्रैबों का केवल अवमूल्यित मूल्य ही द्वितीय वित्तीय वर्ष से आगे के प्रतिलाभ के योग्य होगा।

ग्रेबों के निचले ब्लॉक के बजाय सकल ब्लॉक पर विचार करके सीएचपीटी द्वारा अर्जित अतिरिक्त प्रतिलाभ को उस अवधि के दौरान हुए प्रचालन खर्च में किसी वृद्धि को समायोजित करने वाला माना जा सकता है।

8. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त तर्कों और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण लागत आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए सीएचपीटी द्वारा प्रस्तावित ग्रेबों के निम्नलिखित ग्रेब किराया प्रभार को अनुमोदित करता है :

- (i) सीएचपीटी द्वारा अगस्त, 1997 से पूर्व-प्रभाव से भारत के राजपत्र में इस आदेश के अधिसूचित होने की तारीख तक वसूल किया जा रहा 3.5 घन मीटर के ग्रेब के लिए 1000/- रुपये और 4 घन मीटर के ग्रेब के लिए 1,100/- रुपये का अस्थायी किराया प्रभार।
- (ii) भारत के राजपत्र में इस आदेश के अधिसूचित होने की तारीख से भावी प्रभाव से 3.5 घन मीटर के और 4 घन मीटर के दोनों ग्रेबों के लिए 8 घंटे की अवधि के लिए 1000/- रुपये और 4 घंटे अथवा उसके किसी हिस्से के लिए न्यूनतम 500/- रुपये का एकसमान किराया प्रभार।

9. तदनुसार, सीएचपीटी की दरों के मान में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:

- (i) पुस्तिका-I, अध्याय-IX, मान-घ के अधीन - प्लवमान क्रेनों और साधित्र आदि के लिए प्रभार, श्रेणी-II में क्रम सं. 8 के पश्चात नए क्रम सं. 9 को निम्नवत् शामिल किया गया है :

क्रम संख्या और विवरण	किराये की दर (रुपयों में)	किराये की अवधि	न्यूनतम (रुपयों में)	टिप्पणी
9. किसी भी क्षमता की तट क्रेन के साथ जुड़ा हुआ ग्रेब (3.5 घन मीटर और 4 घन मीटर)	1,000/-	8 घंटे की प्रति अवधि	500/-	(क) न्यूनतम प्रभार चार घंटे अथवा उसके किसी हिस्से के लिए होगा। (ख) ग्रेब के लिए किराया प्रभार, जहाँ बर्थ किराया प्रभारों में तट (घाट) क्रेन का प्रयोग शामिल है, उसे छोड़कर जिस क्रेन के साथ ग्रेब जुड़ा है उस क्रेन के किराया प्रभारों से अतिरिक्त होगा।
(ii) पुस्तिका-I, अध्याय-XI - बर्थ किराया प्रभार में क्रम सं. 3 के अंतर्गत टिप्पणी में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है : - "3. बोर्ड की दरों के मान के अध्याय-IX की श्रेणी-II (जैसे कि नं. 7 से 9) मान-घ के अधीन किए गए उपबंध के अनुसार ग्रेबों (तट क्रेनों से जुड़े हुए) का किराया जब कभी इन दरों पर जलयान की लदाई और अवतारण कार्य के बल्क कार्गो के प्रहस्तन के लिए किराये पर लिया जाए।"				

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/IV/143/2001/असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2001

No. TAMP/23/2001—CHPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal of the Chennai Port Trust for fixation of hire charges for grabs as in the Order appended hereto.

SCHEDULE**Case No. TAMP/23/2001-CHPT****The Chennai Port Trust (CHPT)**

Applicant**ORDER**

(Passed on this 28th day of June 2001)

This case relates to a proposal received from the Chennai Port Trust (CHPT) for fixation of hire charges for grabs.

2.1. In its proposal, the CHPT has made the following main points:

- (i). The CHPT Scale of Rates prescribes the hire charges as Rs.592/- and Rs.974/- for grabs with the capacity 1½ Cu. Yard and 2½ Cu. Yard respectively.
- (ii). The Government Audit has pointed out that though two different rates are available for hire in the Schedule of Rates, the CHPT had been collecting the hire charges for grabs fitted with cranes at the rate of Rs.296/- per shift (pre-revised rate) irrespective of the capacity which is not in order.
- (iii). The 1½ Cu. Yard and 2½ Cu. Yard capacity grabs were already replaced by 3.5 Cu. m. grabs and 4 Cu. m. grabs for traffic operations. In the light of the objection raised by the Audit, a provisional rate of Rs.1000/- for 3½ Cu. m. grabs and Rs.1,100/- for 4 Cu. m. grabs were recovered from August 1997.
- (iv). The provisional rates were fixed in accordance with a provision in the Scale of Rates which allows discretionary powers to the Chairman (CHPT) to fix the charges for use of the crafts or appliances for which the tariff is not included in the Scale of Rates.
- (v). The hire charges of grabs are now worked out on cost based approach at Rs.1,000/- and Rs.1,100/- per shift for 3.5 Cu. m and 4 Cu. m. grabs capacity respectively.
- (vi). It is, however, proposed to follow a uniform rate of Rs.1000/- for period of 8 hours and a minimum of Rs.500/- for 4 hours or part thereof for both the grabs.

2.2. In view of above, the following amendments in the Scale of Rates have been proposed by the CHPT:

- (i). Book-I under Chapter-IX, Scale-D – Charges for floating craft, appliances etc., Category-II a new serial No.9 may be added after serial No.8. as follows:

Serial Number and Description	Rate of Hire (Rs.)	Period of Hire	Minimum (Rs.)	Remarks
9. Grab (3.5 Cu. Metre and 4 Cu. Metre) Fitted to Shore crane of any Capacity	1,000/-	Per Period of 8 hours.	500/-	(a). Minimum charges shall be for four hours or part thereof. (b). The hire charges for the grab shall be in addition to the charges for the hire of the crane to which the grab is fitted except where the use of shore (wharf) crane is included in the Berth Hire charges.

"

224761/01-3

- (ii). The existing serial No.3 under Chapter-XI, Berth Hire, in Book-I of the Scale of Rates may be deleted and substituted as under:

“ 3. Hire of Grabs, (fitted to the Shore Cranes) whenever hired for handling bulk cargo of vessel's loading and unloading work at the rates, as provided under Category-II (such as Nos. 7 to 9) Scale-D of Chapter-IX of the Board's Scale of Rates.”

2.3. It has further proposed to increase the proposed rates by applying the appropriate percentage hike as approved by the TAMP in general revision of Scale of Rates for cranaage with effect from 10 April 2000. (This Authority approved a 100% increase for cranaage / FLT in the case of CHPT vide its Order dated 22 March 2000 which was notified in the Gazette of India on 10 April 2000).

3. The proposal of the CHPT was circulated to all concerned users / representative bodies of port users for their comments. The comments received from them are summarised below:

The Chennai Custom House Agents' Association (CCHAA)

The proposal put-forth by the Chennai Port Trust is reasonable.

Tamil Nadu Electricity Board (TNEB)

- (i). The proposed upward revision of grab hire charges from Rs.296/- to Rs.1000/- per shift is exorbitant and unreasonable. The increase proposed is nearly 350%.
- (ii). This will increase the landed cost of coal substantially which in turn will increase the cost of generation, thereby, affecting the public of Tamil Nadu.
- (iii). The TNEB may be accorded a special status and exempted from the proposed increase in grab hire charges.

Indian National Shlpowners' Association (INSA)

- (i). Basis for considering 225 number of shifts in the computation of hire charges has not been explained.
- (ii). Return on capital considered @18% is monopolistic. It shall be frozen at not more than 12%.
- (iii). Rounding off the rates for both the grabs has been done in favour of the port.

The Shipping Corporation of India (SCI)

- (i). The CHPT has estimated the life of the grabs as five years, which is very much on the lower side. Considering the nature of cargo to be handled, the number of shifts shall be at least 360 as against 225 shifts considered in the cost sheet. The cost per shift then will be Rs.617/- and Rs.647/- for 3.5 Cu. m and 4.00 Cu. m grabs respectively.
- (ii). The CHPT has requested the TAMP to approve 100% Increase in the rates fixed by applying the tariff increase approved in the Order relating to general revision of the Scale of Rates notified by the Authority in the Gazette of India on 10 April 2000. As a result the CHPT is proposing to levy an amount of Rs.2000/- for 8 hours and a minimum of Rs.1000/- for 4 hours for part thereof which is very much on the higher side.
- (iii). Since the cost sheet submitted by the CHPT shows a figure of Rs.1000/- per shift for the said grabs, it will not be logical or rational to seek approval for an amount which is higher than the cost shown in the cost sheet.

- (iv). The CHPT is already charging provisional rate of Rs.1000/- for 3.5 Cu. m. grabs and Rs.1100/- for 4.00 Cu. m. grabs, from August 1997 onwards. These figures are in line with the per shift cost shown in their cost sheet. It is, therefore, proposed to maintain the same rates.

Chennai Port Stevedores Association (CPSA)

There is total slump in bulk traffic at the Chennai Port and any further increase by applying the percentage approved by the TAMP with effect from 10 April 2001 will be detrimental to the interest of the Trade.

Chennai Steamer Agents' Association (CSAA)

The users of the grabs are mostly the Stevedores. The TAMP may be guided by the concerned user body which in this case happens to be the Chennai Port Stevedores Association.

4. A copy each of the comments furnished by the users was sent to the CHPT as feed-back information. The CHPT has offered the following further comments on the feed-back information:

- (i). The rate of Rs. 296 per shift referred by the TNEB for 1 ½ Cu. Yard grabs has been revised to Rs.592 per shift with effect from 10 April, 2000.
- (ii). The proposed rate of Rs.1000 for both 3.5 Cu. m. and 4 Cu. m. grabs is very reasonable compared to the pre-revised rate of Rs. 487 for 2 ½ Cu. Yard grab considering the higher carrying / handling capacity of these grabs.
- (iii). No concession in hire charges for such grabs can be given for any port users.
- (iv). The estimated life of the grab is considered as 5 years as per the life norms of different assets fixed by the (then) MOST.
- (v). In the computation of the hire charges 225 shifts has been reckoned with based on past average operational performance.
- (vi). Any increase approved by the TAMP in general revision of Scale of Rates would be applicable on the appliances / equipments which were already in use. As the grab is in use since 1997, the increase of 100% as approved by the TAMP w.e.f. 10 April 2001 has to be applied on the proposed rate of Rs.1000/- per shift. This shall be applicable retrospectively from 10 April 2001.

5. A joint hearing in this case was held at the CHPT premises on 9 May 2001. At the joint hearing, the following submissions were made:

Chennai Port Trust (CHPT)

- (i). The new grabs are additions not replacements.
- (ii). The Govt. circular has also fixed the life of grabs as 5 years.
- (iii). The proposal now is to increase the hire charges from provisional rate of Rs.1000 / 1100 per shift for 3.5 Cu. m / 4 Cu. m grab capacity to Rs.2000/- per shift.
- (iv). We have gone by average number of shifts. We do not know how the SCI says it shall be 360 and not 225 shifts.
- (v). The proposal for regularising the rates of these grabs was somehow missed in the April 2000 general revision proposal.

- (vi). We are doing many things for cost saving, efficiency improvement, etc. These are not relevant for grab as it is a very small equipment.
- (vii). We had been charging a low rate from 1989 to 1991. There was no change in the tariff up to the year 2000. The present rate is based on actuals. If we had proposed this in April 2000, we would have got a 100% increase.
- (viii). We apply 5 years life for these grabs only from 1997.
- (ix). We have to restrict the use of the grab for fertiliser for safety of the grab on density considerations and also due to the transportation time from fertiliser berth to coal berth.

Tamil Chamber of Commerce and Industry (TCCI)

- (i). 5 years life for a grab is too short. It is not used so frequently so as to exhaust its life so fast.
- (ii). The existing rate for 2½ Cu. Yard grab capacity is Rs.974/- per shift. The hire charges proposed for 3.5 Cu.m grab capacity is Rs.2000/- per shift. There is no logical equation.
- (iii). Grab work for at least half year; and, 2 shifts a day. That is how we worked out 360 shifts.
- (iv). There is maintenance repair even for these grabs. There is downtime. That is why we say, the working life of these grabs has to be more.
- (v). April 2000 revision of 100% was with respect to 1991 rates. Grabs rate were fixed in August 1997. On that (recent) base the MBPT can not ask for a 100% increase.

Seaport Logistics

- (i). There is no justification for a 100% increase. The grab handles only 200 MT per shift per ship against a norm of 1500 MT.

A.M. Ahamed Company

- (i). They say this revision is prospective. But, the CHPT has demanded arrears from bulk fertiliser handlers. This was discussed in the Port Users meeting, but, no decision was taken. We are not given 'No Arrear' certificate for Tender purposes.

M/s. Bhoruka Steel

- (i). Grab capacity of 3.5 Cu. m was bought in 1989, but, it is still counted. Where is the consideration for 5 year life?.
- (ii). For a 1989 grab there can not be a 100% increase from Rs.1000/- of 1997. The CHPT must replace the grab if they want such increases.
- (iii). Consideration of 225 shifts is too low a figure. We endorse the observation of the SCI.

SICAL

- (i). Will there be a rebate if the grab breaks down? The Scale of Rates must have a provision for rebate. In such contingencies the labour gang also has to sit idle. We lose on that.
- (ii). Grab is used only for fertiliser. Do not exclude coal. If this is done grab utilisation will increase and, cost will go down.

Tamil Nadu Electricity Board (TNEB)

- (i). Grab is working from 1989. Please take into account that it has worked for 12 years. Depreciation and interest on the cost of the asset gives them 198% return, which is not correct.
- (ii). Consideration of 225 number of shifts appears to be low. But, if it is average of actuals, we have to accept it.

7. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, and taking into account the arguments advanced at the joint hearing, the following position emerges:

- (i). The CHPT levied provisional rates of Rs. 1000/- and Rs. 1,100/- from August 1997 for the grabs of the capacity 3.5 Cu. m. and 4 Cu. m respectively. These provisional rates were fixed by the CHPT based on a provision in the pre-revised Scale of Rates which gave discretionary powers to its Chairman to fix the tariff of such appliances/crafts for which tariff is not prescribed in the Scale of Rates. It will not be congruous with the arrangement envisaged in the MPT Act for tariff setting, if such discretionary powers to fix tariffs are delegated to the regulated entities. Realising this position, the provision giving discretionary powers to the Chairman (CHPT) has already been deleted in the revised Scale of Rates notified by this Authority on 30 March 2001.
- (ii). The CHPT levied the provisional rate from August 1997 and has now arrived at the cost based tariff of Rs.1000/- for both the grabs. The rates being provisional, it was incumbent on the CHPT to regularise them by seeking approval of this Authority at the immediate available opportunity. The CHPT did not do this (even) at the time of the general revision of tariffs effected in the year 2000. It is unfortunate that it took nearly four years to take action to regularise its 'provisional' levy of charges.
- (iii). The CHPT has considered 5 years life for arriving at the depreciation of the assets from 1997. The contention of the TCCI that the 5 years life of the grab is too low cannot be accepted because the CHPT has considered the economic life of 5 years life based on the Govt. guidelines. Incidentally, we have been allowing the life-norms fixed by the Government for computation of tariffs at all the major ports. The depreciation figure estimated by the CHPT need not, therefore, be modified. Without prejudice to the decisions taken above, the point made by the TNEB about the 'life' of one of the grabs in this case deserves consideration. As has been alleged by them, and as has been admitted by the CHPT also, one of the grabs has been working from 1989 i.e., for 12 years; and, there is no proposal to scrap it even now.

Three points arise for consideration:

- (a). In this backdrop, can a 5-year life prescription be said to be justified?
- (b). As demanded by M/s. Bhoruka Steel, should the CHPT be required to replace the grab with a new one if any increase in tariff is to be considered?
- (c). As represented by the TNEB, the return on this fully paid-up asset is phenomenal. Should the CHPT be required, therefore, to fix the tariff in this case differently?

As has already been stated, this Authority has been allowing the life-norms fixed by the Government. In this case, the life-norm so fixed is five years. That being so, no change in the norm is needed. The point agitated by the TNEB about a fully paid-up asset is not wholly correct because fully paid-up assets are excluded from the 'net block' which alone is reckoned with for purposes of computing return on capital employed. Nevertheless, it has to be considered that the tariff base at the existing rate incorporates an element of this factor. This will have to be so unless this Authority is in a position to adopt the marginal cost pricing system the introduction of which is fraught with complexities and, in any case, is in a very preliminary stage of

224761/2001-4

consideration. The demand of M/s. Bhoruka Steel, however, is worthy of attention. If the CHPT are to increase the tariff for an equipment which is being operated for beyond its technical life-span, then, the users can have a legitimate expectation of it to replace the old equipment with a new one. The CHPT is, therefore, so advised and required to cover this point at the time of the next (concerned) revision.

- (iv). The CHPT has considered a return of 18% as against 19.5% allowed in the other cases by this Authority reckoning with 13.5% towards interest on Govt. loans and 6% (3+3) towards a Development Fund and a Renewal Fund. The impact of this differential of 1.5% shall be around Rs.26-28 per shift. Since the CHPT has rounded off the rates from Rs.987/- and Rs.1036 for 3.5 Cu. m. and 4 Cu. m capacity grab to Rs.1000/- and Rs.1100/-, the modification in ROCE working to the extent of Rs.26/- will be negligible and therefore, ignored.
- (v). The TCCI and a few other users have contended that 225 number of shifts considered by the CHPT is too low; and, at least 360 shifts shall be reckoned with in the computation of hire charges. The CHPT has, however, clarified that 225 number of shifts considered by them is based on the average of past actuals. In this context, the estimation of the CHPT seems reasonable as they are based on an average of past actuals and, therefore, is accepted. Significantly, even the TNEB, a main-user, has conceded that 'if the CHPT computation is based on average of actuals it has to be accepted.'
- (vi). Although the cost estimates for the two grabs are different, the CHPT has proposed a uniform tariff for both the grabs. There is no significant difference in the provisional rates levied by the CHPT and the rates proposed on a cost based approach. Also, considering the points discussed at (iii), (iv) and (v) above, the rate proposed by the CHPT is found to be reasonable and, therefore, is approved.
- (vii). This Authority does not generally approve tariffs with retrospective effect unless some exceptional special circumstance prevails. Since, these grabs are in use since 1997 for which provisional rates are being collected even now, the provisional hire charges levied by the CHPT retrospectively from August 1997 need to be considered for ex-post facto approval in order to ratify the action taken by the CHPT. The CHPT is, however, advised to refrain from presenting such 'fait accompli' cases before this Authority in future. The CHPT has proposed one rate now for both the grabs although earlier, in their provisional arrangement, they had adopted two different rates. The one rate now proposed is a step towards simplification; and, since the lower rate has been retained, it can also be said to be a concession to users. This concession, however, incidentally, raises a point about some 'excess recovery' in some cases. Bearing in mind the altruistic intentions of the CHPT that have given rise to this (unanticipated) problem, it will not be necessary to require the CHPT to refund the 'excess' recovered.

Bearing in mind this position, this Authority decides to approve the revised tariffs in two phases. In phase-I (i.e., from August 1997 to the date of notification of this Order), the 'provisional rates' charged by the CHPT; and, in phase-II (i.e., prospectively from the date of notification of this Order onwards), the single rate of Rs.1,000/- for both the grabs.

- (viii). The CHPT has proposed to increase the hire charges by 100% based on the tariff increase approved by this Authority in the April 2000 general revision case.

It is to be noted in this context that the tariff increase approved by this Authority in the general revision case was based on surplus/deficit position reflected in the cost statements. The CHPT had not incorporated any provision to fix the tariff of these two grabs in the general revision proposal. It, therefore, appears that cost elements relevant to these grabs were not included in the cost statements submitted at that point of time. That being so, the 100% increase over the cost based tariff for the two grabs proposed by the CHPT now is not approved.

Further, the following facts are also relevant in this context:

- (a). The hire charges are fixed with reference to estimates. Actual income & expenditure during the past 4 years on hire of the relevant grabs have not been provided by the CHPT.
- (b). Return on capital employed is on the depreciated value of the asset. In this case acquisition cost has been taken for determining the return, since the computations of hire charges has been made based on cost of the facility. If costing of activity/service, as done in the case of general revision of tariff, is considered, then, only the depreciated value of grabs will qualify for return from the second financial year onwards.

The additional return earned by the CHPT by considering the gross block of the grabs instead of net block of the grabs can reasonably be assumed to offset any increase in the operational expenditure incurred during the period.

8. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves, the following hire charges of grabs proposed by the CHPT following a cost based approach:

- (i). Provisional hire charge of Rs.1000/- for 3.5 Cu. m. grabs and Rs.1,100/- for 4 Cu. m. grabs being levied by the CHPT with retrospective effect from August 1997 till the date of notification of this Order in the Gazette of India.
- (ii). A uniform hire charge of Rs.1000/- for the period of 8 hours and a minimum of Rs.500/- for 4 hours or part thereof for both 3.5 Cu. m. grabs and 4 Cu. m grabs with prospective effect from the date of notification of this Order in the Gazette of India.

9. Accordingly, the Scale of Rates of the CHPT is amended as follows:

- (i). A new Serial No. 9 after the Serial no. 8 in Book-I under Chapter- IX, Scale D – Charges for floating cranes and appliance, etc., Category-II is inserted as follows:

Serial Number and Description	Rate of Hire (Rs.)	Period of Hire	Minimum (Rs)	Remarks
9. Grab (3.5 Cu. metre and 4 Cu. metre) Fitted to Shore crane of any Capacity	1,000/-	Per Period of 8 hours.	500/-	(a).Minimum charges shall be for four hours or part thereof. (b). The hire charges for the grab shall be in addition to the charges for the hire of the crane to which the grab is fitted except where the use of shore (wharf) crane is included in the Berth Hire charges.

- (ii). The note under S.No.3 in Book –I, Chapter XI – Berth hire charges is amended as follows:

“3. Hire of Grabs, (fitted to the Shore Cranes) whenever hired for handling bulk cargo of vessel's loading and unloading work at the rates, as provided under Category-II (such as Nos. 7 to 9) Scale-D of Chapter-IX of the CHPT's Scale of Rates.”

S SATHYAM, Chairman

[No Advt /III/IV/143/2001-Exty]

